राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धांत
(Directive Principles of State Policy)

मौलिक अधिकारों का अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा। यदि संविधान के चौथे भाग में वर्णित निर्देशक सिद्धांतो का अध्ययन न किया जाये। मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को अलग-अलग स्थान दिया गया है। तथा मौलिक अधिकारो को न्यायालयों द्वारा न्याय - मान्य व निर्देशक तत्वो को न्यायालय द्वारा न्याय - अमान्य घोषित किया गया है।

~~संविधान का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता~~
~~(Meaning and Necessity of the Constitution~~

सरल शब्दों मे राज्य के संविधान की परिभाषा लिखित तथा अलिखित नियमों एवं विनियमों के निकाय के रूप में की जा सकती है, जिनके द्वारा सरकार का गठन होता है। और वह कार्य करती है। यह अलग बात है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के घोषणापत्र के रूप में व्यक्तियों तथा उनके राज्य के बीच ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध को स्पष्ट करने हेतु कुछ और सिद्धांतों को अंगीकार करें।

~~राजनीतिक सिद्धांत~~

राजनीतिक सिद्धान्त

राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता (Relevance of Political theory)

हमारे अध्ययन के किसी भी विषय को एक स्वायत्त अनुशासन (discipline) बनाने के लिए उसमें स्वयं को दिशा निर्देश तथा विकसित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। एक स्वतन्त्र अनुशासन (विषय) के लिए यह आवश्यक है कि उसका अपना विषय क्षेत्र स्पष्ट एवं निश्चित हो। मान्यता हो। उसकी अध्ययन सम्बन्धी मान्यता हो। एवं विकसित पद्धतियां तथा